RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2019-2021 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com

www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 11 NOVEMBER TO 17 NOVEMBER 2020 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 06 ■ अंक 12 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

अपना पहला एग्रीकल्चर कमोडिटी फ्यूचर्स एग्रीमेंट लॉन्च करेगा एनएसई Page 2

टाटा स्काय बिंज ने अपनी व्यापक कंटेंट लाइब्रेरी को किया विस्तारित Page 5

17 साल बाद सर्वार्थसिद्धि योग में दिवाली Page 6

editoria!

रास्ता बदले बिहार

चुनाव आयोग का आंकड़ा है कि बिहार में मौजूदा विधानसभा चुनावों के दौरान ही करीब 25 करोड़ रुपये मूल्य की गैरकानूनी शराब जब्त की गई है। यह मात्रा 2019 के आम चुनाव और 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान जब्त की गई शराब से ज्यादा है। राज्य में शराबबंदी की नीति की क्या गत हुई है, इसका इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? हालांकि ऐसे सबूत हमें बार-बार अलग-अलग राज्यों में मिलते रहे हैं। देश का कोई भी ऐसा राज्य या क्षेत्र नहीं है जहां शराबबंदी को पूरी तरह सफल माना जा सके। बिहार में भी यह आरोप आम रहा है और बातचीत के दौरान भी लोग बताते हैं कि अवैध शराब की खरीद-बिक्री हो ही रही है, बस पहले की तरह खुलकर नहीं होती। जो काम पहले वैध तौर पर, पारदर्शिता के साथ, टैक्स जमा करके होता था, वही अब अपराध की तरह ढके-छुपे ढंग से और पुलिस-प्रशासन की सांठगांठ से किया जा रहा है। इससे जहां एक तरफ सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है, खजाना खाली होने के कारण जरूरी सरकारी नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं, वहीं राज्य में भ्रष्टाचार और आपराधिक प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिल रहा है। जहां तक लोगों के स्वास्थ्य और उनकी आदतों के सुधरने का सवाल है तो चूंकि चोरी-छुपे शराब उपलब्ध हो ही रही है, इसलिए उस मोर्चे पर भी कोई खास फायदा नहीं है। उलटे ऐसी आशंका बढ़ जाती है कि सस्ती और अवैध दारू के चक्कर में लोग जहरीली शराब के शिकार न बन जाएं। विभिन्न राज्यों में समय-समय पर ऐसी मौतें अखबारों की सुर्खियां बनती रहती हैं। खुद बिहार सरकार के आंकड़े बताते हैं कि लॉकडाउन से पहले तक 2 लाख 60 हजार लोगों पर दारूबंदी के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था। कोर्ट में लंबित होने के चलते ऐसे मामले और बढ़ गए हैं। आज भी हाईकोर्ट में 40 हजार जमानत याचिकाएं अटकी हुई हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो जमानत राशि न जुटा पाने की वजह से जेल में पड़े हुए हैं। स्वाभाविक रूप से इसका खामियाजा उनके परिवार वालों को भुगतना पड़ रहा होगा। इन तमाम मुसीबतों के पीछे वजह सिर्फ एक है- बुराइयों को दूर करने का गलत तरीका। बेशक, शराब एक बुराई है, जिसका अतिरेक व्यक्ति का स्वास्थ्य, धन और परिवार तक नष्ट कर सकता है। लेकिन सवाल यह है कि इस बुराई को नियंत्रित कैसे किया जाए। अब तक के अनुभव बार-बार साबित करते रहे हैं कि नशाखोरी जैसी आदतें कड़े कानून बनाकर और सख्त सजाएं देकर नहीं दूर की जा सकतीं, अलबत्ता इस कोशिश में भ्रष्टाचार जैसी अन्य कई बुराइयां जरूर जोर पकड़ने लगती हैं। बिहार में भी यही होता दिख रहा है। वक्त आ गया है कि बार-बार नाकाम साबित हुई शराबबंदी की नीति को लागू करते हुए उसका नुकसान उठाते रहने के बजाय इस नीति को पलटने का फैसला किया जाए। उम्मीद करें कि चुनाव नतीजों के बाद बिहार में बनने वाली नई सरकार अब तक के अनुभवों की रोशनी में उचित फैसला करने में देर नहीं लगाएगी।

नवंबर के महीने में क्रूड ऑइल की कीमत में आग

जानिए कितना हुआ महंगा

नई दिल्ली। एजेंसी

कोरोना वैक्सीन को लेकर आने वाली पॉजिटिव खबरों से सोना और चांदी की की कीमत में गिरावट आई और इक्विटी मार्केट में तेजी देखने को मिली। वहीं दूसरी ओर इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में बीते तीन दिनों से लगातार इसका जगरदस्त असर देखने को मिल रहा है। ब्रेंट और डब्ल्यूटीआई क्रूड ऑयल की कीमत में 12 फीसदी से ज्यादा देखने को मिल चुकी है। जहां ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम 45 डॉलर प्रति बैरल के आसपास आ गए हैं। जबकि डब्ल्यूटीआई के दाम में 43 डॉलर प्रति बैरल के बेहद करीब है।

क्रूड ऑयल की कीमत में इजाफा

वैक्सीन की रिपोर्ट आने के बाद ब्रेंट और डब्ल्यूटीआई की कीमत में इजाफा देखने को मिला है। पहले डब्ल्यूटीआई की कीमत की बात करें तो 9 नवंबर को 39 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। वैक्सीन की खबरों के आने के बाद तेजी देखने को मिली। तब से अब तक 4 डॉलर प्रति बैरल का इजाफा देखने को मिल चुका है। मौजूदा समय में डब्ल्यूटीआई के दाम 42.75 डॉलर प्रति बैरल पर आ चुका है।

नवंबर के महीने में जबरदस्त तेजी

अगर बात पूरे नवंबर की करें तो ब्रेंट और डब्ल्यूटीआई में 9 डॉलर प्रति बैरल तक का इजाफा देखने को मिल चुका है। नवंबर के महीने से पहले डब्ल्यूटीआई के दाम 34 डॉलर प्रति बैरल पर थे। जबकि ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत नवंबर से पहले 36 डॉलर था। नवंबर के महीने में ब्रेंट की कीमत में काफी तेजी देखने को मिल चुकी है।

क्रूड ऑयल की कीमत में तेजी के कारण

नवंबर में एलएमई एल्युमीनियम की कीमत 1920 डॉलर के साथ18 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। जबकि भारतीय वायदा बाजार में एल्युमीनियम 157 रुपए के स्तर पर कारोबार कर रहा है। कीमत में तेजी की असली वजह कोरोनो वायरस वैक्सीन के मोर्चे पर हाल ही में सकारात्मक विकास की वजह से निवेशकों में बेहतर रिस्पांस देखने को मिल रहा है। पिछले महीने की तुलना में एल्युमीनियम की कीमत ऊपर की ओर बढ़ी है, जो 5 अक्टूबर के बाद से 8 फीसदी से ज्यादा है। वैश्विक आर्थिक रिकवरी में अनिश्चितता अभी भी मौजूद है। अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में बिडेन का चुनाव कोविड-19 के नियंत्रण के लिए अनुकूल है। आर्थिक प्रोत्साहन बिल के पैमाने पर अमरीका में अभी भी दोनों पक्षों के बीच मतभेद हैं, और बाजार में अभी भी कई अनिश्चितताएं हैं। केंद्रीय बैंकों के पास मध्यम अवधि में अपने आक्रामक रुख को बदलने की संभावना नहीं है। वैक्सीन आने के बाद भी मुद्रास्फीति और श्रम बाजार के पिक-अप पकड़ने में समय लेगा। कोरोनो वायरस वैक्सीन के विकास में प्रगति की वजह से क्रूड ऑयल की कीमत में इजाफा हुआ है। जिससे संकेत मिलता है कि जल्द ही ग्लोबल इकोनॉमी में तेजी आने की संभावना है। फाइजर इंक ने कहा है कि उनकी स्टडी के शुरुआती आंकड़ों के आधार पर कोविड-19 को रोकने के लिए इसका प्रयोगात्मक टीका 90 फीसदी से अधिक प्रभावी है।

क्या कहते हैं जानकार

केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया के अनुसार कोरोना वायरस के इस दौर में वैक्सीन की पॉजिटिव खबरें आना क्रूड ऑयल की कीमत को सपोर्ट कर रहा है। खासकर नवंबर के महीने में अच्छी तेजी देखने को मिली है। इससे पहले प्रोडक्शन की कट की संभावनाओं को बल मिला है। साथ इंटरनेशनल मार्केट में अभी थोड़ी अस्थिरता बनी हुई है। अगर वैक्सीन मार्केट में जल्दी आती है तो क्रूड ऑयल की कीमत में और इजाफा देखने को मिल सकता है।

भारत ने ओपेक से कच्चे तेल की कीमतों में विसंगति दूर करने को कहा

नयी दिल्ली। एजेंसी

भारत ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से विभिन्न क्षेत्रों के लिए कच्चे तेल की कीमतों में अंतर से संबंधित विसंगतियों को दूर करने को कहा है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक है। इसके साथ ही भारत ने कोविड-19 की वजह से वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र की आपूर्ति श्रृंखला में आई अड़चनों का आकलन करने पर भी जोर दिया। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बृहस्पतिवार को भारत-ओपेक ऊर्जा वार्ता की चौथी उच्चस्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि ओपेक भारत की 78 प्रतिशत तेल की मांग को पूरा करता है। इसके अलावा वह भारत की एलपीजी की 59 प्रतिशत और एलएनजी की 38 प्रतिशत जरूरत को पूरा करता है। भारत ने 2019-20 में ओपेक देशों से 92.8 अरब डॉलर के हाइड्रोकॉर्बन का आयात किया था। प्रधान ने कहा कि इस महामारी से वैश्विक तेल एवं गैस उद्योग प्रभावित हुआ है। तेल की मांग के साथ ही महामारी ने आपूर्ति पक्ष पर भी असर डाला, जिससे वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव आया है।

(शेष पृष्ठ 2 पर)

अपना पहला एग्रीकल्चर कमोडिटी फ्यूचर्स एग्रीमेंट लॉन्च करेगा एनएसई

क्रूड डीगम्ड सोयाबीन ऑयल (सीडीएसओ) के लिए फ्यूचर्स एग्रीमेंट 1 दिसंबर, 2020 को लॉन्च होगा

मुंबई। एजेंसी

भारत का प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई), 1 दिसंबर, 2020 को क्रूड डीगम्ड सोयाबीन ऑयल (सीडीएसओ) के लिए अपना पहला एग्रीकल्चर कमोडिटी फ्यूचर्स एग्रीमेंट लॉन्च करेगा। यह एग्रीमेंट मंथली एक्सपायरी कैश सेटल्ड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी ट्रेडिंग लॉट साइज 10 एमटी है और प्राइस बेसिस कांडला है। भारत दुनिया में खाद्य तेलों का सबसे बड़ा इम्पोर्टर है। यह फ्यूचर्स एग्रीमेंट भारतीय कमोडिटी डेरिवेटिव्स इकोसिस्टम का अनुपस्थित लिंक उपलब्ध करायेगा, और भारत तथा विदेशों में सोयाबीन ऑयल्स प्रोसेसिंग और संबद्ध उद्योगों को सुविधा प्रदान करेगा, जो उनके मूल्य जोखिम के प्रबंधन के मामले में प्रतिरक्षा के लिए एक आदर्श हेजिंग टूल है।

एग्रीकल्चर कमोडिटी फ्यूचर्स एग्रीमेंट की शुरुआत एनएसई के मिशनमें एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है। 25 साल पहले शुरू हुआ यह मिशन प्रॉडक्ट्स और सेवाओं को बाजार में लाने की सुविधा प्रदान करता है। हमारे मौजूदा प्रॉडक्ट्स की सूची में एग्रीकल्चर प्रॉडक्ट्स को शामिल करना, ब्रोकिंग समुदाय को एक ही प्लेटफॉर्म ट्रेड करने और क्लीयर करने के लिए एनएसईका पूरा लाभ प्रदान करता है।

एनएसई के एमडी और सीईओ, श्री विक्रम लिमये ने कहा कि 'एनएसई सुविधाजनक और लागत प्रभावी ऑनशोर हेजिंग प्रॉडक्ट प्रदान करके भारतीय कमोडिटी बाजारों को मजबूत बनाने के लिए समर्पित है। भारत दुनिया में खाद्य तेलों के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है, इसलिए कच्चे सोयाबीन तेल के लिए एक कुशल हेजिंग सिस्टम की भी आवश्यकता है। यह प्रॉडक्ट आम तौर पर बाजार सहभागियों और कमोडिटी इकोसिस्टम के लिए सही मूल्य जोखिम प्रबंधन टूल के रूप में काम करेगा।'

इस अवसर पर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एसईए) ने एनएसई को बधाई दी है। एसईए के एक्जिक्यूटिव डायरेक्टर डॉ. बीवी मेहता ने कहाकि 'एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत ही उपयोगी टूल है जो उद्योग के लिए मूल्य जोखिम प्रबंधन को सुविधाजनक और आसान बनाता है। मुझे यकीन है कि हमारे सदस्य इन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स को अपने रोजाना के व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए भी उपयोगी पायेंगे। आगे इस तरह के और फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स को शुरू किया जाना चाहिए, ताकि हम भारत में एक जीवंत कमोडिटी मार्केट्स इकोसिस्टम बना पायें।'

इंडियन ऑयल ने दरभंगा में खोला 120वां विमान ईंधन स्टेशन

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

सार्वजनिक क्षेत्र की इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने बिहार के दरभंगा में अपना 120वां विमान ईंधन स्टेशन शुरू किया। कंपनी ने सोमवार को एक बयान में कहा, ''इस ईंधन स्टेशन का उद्घाटन स्पाइसजेट के दिल्ली जाने वाले एक विमान में भरकर किया। इसी के साथ इस हवाईअड्डे से उड़ानों का परिचालन भी शुरू किया।'' इंडियन ऑयल की देश के ईंधन बाजार में 40 प्रतिशत हिस्सेदारी है। क्षेत्रीय हवाई संपर्क (उड़ान) योजना के तहत विकसित किए गए इस हवाईअड्डे पर ईंधन भरने की सुविधा विकसित करने के लिए कंपनी का चयन नागर विमानन मंत्रालय ने 2018 में किया था। हवाईअड्डे को चालू करने के लिए कंपनी ने यहां ट्रक से ईंधन उपलब्ध कराने की सुविधा शुरू की है। कंपनी ने कहा कि स्थायी सुविधा 2020 के अंत तक शुरू हो जाएगी।

गेल का दूसरी तिमाही का मुनाफा 9 प्रतिशत घटा, गैस परिवहन कारोबार से हुआ ये नुकसान

नई दिल्ली। एजेंसी

देश की सबसे बड़ी गैस आपूर्ति करने वाली कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड का शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 8.5 प्रतिशत घट गया। कंपनी को गैस परिवहन कारोबार में नुकसान हुआ। गेल ने शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा है कि चालू वित्त वर्ष की जुलाई से सितंबर तिमाही के दौरान कंपनी का एकीकृत शुद्ध लाभ 1,068.16 करोड़ रुपये रहा है। प्रति शेयर लाभ 2.47 रुपये बैठता है।

वहीं एक साल पहले इसी तिमाही का उसने 1,167.58 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया था। तब प्रति शेयर लाभ 2.59 रुपये रहा था। आलोच्य अवधि में गेल का कुल कारोबार 23.7 प्रतिशत घटक,.80 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इस दौरान गैस के दाम कम रहने के कारण कंपनी का कारोबार कम रहा। कंपनी को महामारी के कारण मांग प्रभावित होने की वजह से प्राकृतिक गैस के विपणन कारोबार में 334.55 करोड़ रुपये का कर पूर्व नुकसान हुआ।

हालांकि, पहली तिमाही में उसका कर पूर्व नुकसान 614.06 करोड़ रुपये रहा था। एक साल पहले कंपनी को जुलाई-सितंबर तिमाही में 241.72 करोड़ रुपये का करपूर्व मुनाफा हुआ था। गेल ने कहा है, ''कोविड- 19 महामारी की वजह से दुनियाभर में और भारत में सामान्य कारोबारी गतिविधियों पर असर पड़ा और इससे आर्थिक गतिविधियां धीमी पड़ी।'' कंपनी ने यह भी कहा है कि उसके भौतिक प्रदर्शन में अप्रैल- जून तिमाही के मुकाबले सुधार आया है और यह करीब करीब सामान्य स्तर पर पहुंच गई हैं।

भारत ने ओपेक से कच्चे तेल की कीमतों में विसंगति दूर करने को कहा

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उन्होंने कहा, ''यूरोप के कई देशों में दूसरे दौर के लॉकडाउन तथा कच्चे तेल की कीमतों पर इसके तात्कालिक असर के संकेत देखने को मिल रहे हैं।'' प्रधान ने कहा कि भारत और ओपेक को वैश्विक स्तर पर ऊर्जा क्षेत्र विशेषरूप से तेल एवं गैस क्षेत्रों में आ रहे बदलावों को गहराई से देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे हम संयुक्त रूप से मौजूदा दौर में और कोविड-19 के बाद के परिदृश्य में ऊर्जा चुनौतियों का मुकाबला कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि महामारी और उसकी वजह से लागू लॉकडाउन के चलते दुनियाभर में मांग प्रभावित हुई है। इससे कच्चे तेल की उपलब्धता बहुत ज्यादा हो गई है, जिसकी वजह से कीमतें नीचे आई हैं। प्रधान ने कहा, ''कोविड-19 की वजह से वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र की आपूर्ति श्रृंखला में आई अड़चनों का आकलन करने की जरूरत है। प्रधान ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि ओपेक सचिवालय सदस्य देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में कच्चे तेल की कीमतों में अंतर से जुड़ी विसंगतियों को दूर करने के लिए बात करेगा। हालांकि, उन्होंने इन विसंगतियों का खुलासा नहीं किया। परंपरागत रूप से ओपेक देश पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं को पूर्वी देशों की तुलना में कच्चे तेल की बिक्री में काफी छूट या रियायत देते हैं।

पेट्रोनेट एलएनजी की अगुवाई करेंगे आईओसी के निदेशक एके सिंह

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) के पाइपलाइन व्यवसाय के अक्षय कुमार सिंह देश के सबसे बड़े गैस आयातक पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के नये प्रबंध निदेशक (एमडी) एवं मुख्य कार्यकारी (सीईओ) होंगे। पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड ने अपनी वेबसाइट पर एक संक्षिप्त नोटिस में बताया कि प्रभात सिंह का पांच साल का कार्यकाल 13 सितंबर को पूरा हो गया। एके सिंह उनकी की जगह लेंगे। कंपनी ने कहा, ''पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड (पीएलएल) के निदेशक मंडल ने चार नवंबर 2020 को हुई बैठक में अक्षय कुमार सिंह को एमडी एवं सीईओ पद के लिये चुना है।'' इस चयन के साथ ही एके सिंह पुनः गैस के व्यवसाय में लौट गये हैं। वह 2018 में आईओसी के निदेशक मंडल में शामिल होने से पहले सरकारी गैस कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक थे। उन्होंने एमआईटी मुजफ्फरपुर (बिहार) से मैकेनिकल इंजीनियरिंग और दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। उनके पास तेल एवं गैस उद्योग में लगभग 34 वर्षों का अनुभव है। सूत्रों ने कहा कि उन्हें पीएलएल बोर्ड की एक खोज-सह-चयन समिति द्वारा चुना गया है।

ओएनजीसी ने पुराने तेल, गैस फील्ड से उत्पादन बढ़ाने के लिए बोली आमंत्रित की

नयी दिल्ली। एजेंसी

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ओएनजीसी ने अपने पुराने तेल और गैस फील्ड से उत्पादन बढ़ाने के लिए वैश्विक कंपनियों से बोली आमंत्रित की हैं। निविदा दस्तावेज के अनुसार 15 वर्षीय उत्पादन संवर्धन करार (पीईसी) के लिए कंपनियों को पूंजी और परिचालन खर्च में निवेश करने के लिए प्रतिबद्धता जतानी होगी, ताकि उत्पादन को मौजूदा स्तर से बढ़ाया जा सके। तय स्तर से ऊपर उत्पादन बढ़ने पर तेल और गैस के लिए अमेरिकी डॉलर में शुल्क का भुगतान किया जाएगा। इस संबंध में ओएनजीसी ने 27 अक्टूबर को अभिरुचि पत्र (ईओआई) जारी कर बाहरी ठेकेदारों से पुराने फील्ड के लिए 15 साल के पीईसी की पेशकश की। कंपनी ने यह नहीं बताया इन फील्ड की संख्या कितनी है। कंपनी ने तेल या गैस फील्ड के नामों का उल्लेख भी नहीं किया है। हालांकि, सूत्रों ने कहा कि देश के सबसे पुराने उत्पादक क्षेत्र बड़े पैमाने में असम और गुजरात में हैं।

बैंक रूपे कार्ड, यूपीआई भुगतान ऐप को बढ़ावा दें: सीतारमण

मुंबई। एजेंसी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बैंकों से 'केवल रूपे कार्ड ' को बढ़ावा देने को कहा। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) भारत के एक दिग्गज उत्पाद ब्रांड की ख्याति अर्जित करे। सीतारमण ने बैंकों से यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के साथ डिजिटल तरीके से भुगतान पर जोर देने एवं गैर-डिजिटल भुगतान को यथासंभव हतोत्साहित करने को कहा। भारतीय बैंक संघ (आईबीए) की 73वीं सालाना आम बैठक को संबोधित करते हुए सीतारमण ने बैंकों को सभी खातों को संबंधित ग्राहकों की आधार संख्या से जोड़ने का काम दिसंबर तक पूरा करने को भी कहा। अगर यह उस समय तक पूरा नहीं होता है, तब इसे 31 मार्च, 2021 तक पूरा किया जाना चाहिए। देश में खासकर कोरोना वायरस महमारी के बीच डिजिटल और संपर्क रहित भुगतान पर जोर के साथ वित्त मंत्री ने डिजिटल भुगतान माध्यम को बढ़ावा देने की बात कही। सीतारमण ने कहा कि रूपे का उपयोग दुनिया भर में हो रहा है, ऐसे में इसके अलावा कोई अन्य कार्ड देने का मतलब नहीं बनता। रूपे भुगतान कार्ड है जिसे एनपीसीआई ने जारी किया। रिजर्व बैंक और आईबीए की पहल एनपीसीआई देश में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली का शीर्ष संगठन है। उन्होंने कहा, "... जब रूपे वैश्विक हो गया है, तब ऐसे में मुझे नहीं लगता कि भारतीयों को रूपे के अलावा अन्य कार्ड दिये जाएं। अतः रूपे कोर्ड को

बढ़ावा दीजिए। यह सुनिश्चित कीजिए कि एनपीसीआई ब्रांड इंडिया उत्पाद बने...।" मंत्री ने यह बात ऐसे समय कही है जब सरकार आत्मनिर्भर भारत अभियान को जोर-शोर से बढ़ावा दे रही है। उन्होंने यह भी कहा कि बैंकों को डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित और अन्य रूप से किये जाने को वाले भुगतान को हतोत्साहित करना चाहिए। उन्होंने यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) आधारित भुगतान को अपनाने पर भी जोर दिया। वित्त मंत्री ने कहा, "यूपीआई हमारे सभी बैंकों में आम बोलचाल का शब्द होना चाहिए।" एनपीसीआई द्वारा विकसित यूपीआई यानी एकीकृत भुगतान व्यवस्था के जरिये मोबाइल फोन के माध्यम से एक बैंक खाते से दूसरे खाते में तुरंत पैसे का अंतरण किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेश की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। अभी इसे आगे बढ़ाना बाकी है। कई ऐसे खाते हैं, जो अबतक आधार से नहीं जुड़े हैं। सीतारमण ने कहा कि प्रत्येक खाता 31 मार्च, 2021 तक आधार से जुड़ना चाहिए और जहां भी जरूरी तथा लागू हो, पैन (स्थायी खाता संख्या) से उसे संबद्ध किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "दिसंबर तक सभी खातों को आधार से जोड़े। अगर यह उस समय तक पूरा नहीं होता, इसे 31 मार्च, 2021 तक पूरा किया जाए। साथ ही जहां भी लागू हो, खातों को पैन से संबद्ध किया जाए।" बैंकों के विलय के बारे में वित्त मंत्री ने कहा कि उनकी इच्छा है कि जिन बैंकों में दूसरे बैंकों का विलय हुआ है, वे भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की तरह बड़े वित्तीय संस्थान बने। उन्होंने कहा, "विलय के बाद हमारे पास देश में आठ और एसबीआई जैसे बैंक हो सकते हैं। मुझे भरोसा है कि आप अपनी ऊर्जा इस बात में लगाएंगे कि इस दिशा में कितना बेहतर किया जा सकता है। केवल आकार ही नहीं बल्कि यह भी देखना है कि बैंक विविध गतिविधियों में शामिल हों। भारत का बड़े बैंकों पर जोर है।" वित्त मंत्री ने यह भी कह कि बैंकों को जमीनी स्थिति को समझना चाहिए और ग्राहकों और उनकी जरूरतों को लेकर संवेदशील होने की जरूरत है। बैंकों को ग्राहकों का वैध चिंताओं का समाधान करना चाहिए। कार्यक्रम में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अर्थव्यवस्था में पुनरूद्धार के संकेत दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस समय सबसे जरूरी है कि उत्पादक क्षेत्रों को ऋण का प्रवाह हो और बैंकों की इस संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। वित्तीय सेवा सचिव देबाशीष पांडा ने कहा कि बैंक को प्रौद्योगिकी अपनाने और उसके उपयोग पर जोर होना चाहिए। उन्होंने बैंकों से वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनियों से गठजोड़ करने को कहा ताकि डिजिटल तरीके से कर्ज व्यवस्था को बढ़ावा मिले।

अगले साल से इन कंपनियों के लिए अनिवार्य होगा जीएसटी ई-बिल

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

अगले साल से उन फर्मों के लिए जीएसटी ई-इनवॉइसिंग (GST E-invoicing) अनिवार्य होगा जिनका टर्नओवर 100 करोड़ रुपये से अधिक है। पहले यह लिमिट 500 करोड़ रुपये थी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स (CBIC) ने मंगलवार को इस बारे में अधिसूचना जारी की। इसमें कहा गया है कि जीएसटी काउंसिल की सिफारिश पर यह बदलाव किया गया है। यह व्यवस्था 1 जनवरी, 2021 से लागू होगी। इस बदलाव से बड़ी संख्या में मझोली कंपनियां ई-इनवॉइसिंग के दायरे में आ जाएंगी। माना जा रहा है कि 1

अप्रैल 2021 से इसे सभी टैक्सपेयर्स के लिए इसे बी2बी ट्रांजैक्शन के वास्ते अनिवार्य बना दिया जाएगा। केएमपीजी इंडिया में पार्टनर (इनडायरेक्ट टैक्सेज) हरप्रीत सिंह ने कहा कि 100 करोड़ से 500 करोड़ रुपये तक टर्नओवर वाले डीलरों को ई-इनवॉइसिंग के दायरे में लाना इकॉनमी के फॉर्मेलाइजेशन की दिशा में एक और कदम है।

1 अक्टूबर से लागू हुई थी व्यवस्था

इसके क्रियान्वयन में शुरुआत में कुछ परेशानी हो सकती है लेकिन लॉन्ग टर्म में इससे ज्यादा पारदर्शिता आएगी, कर व्यवस्था बेहतर होगी और कर अनुपालन तथा फाइलिंग में ऑटोमेशन होगा। बिजनस टु बिजनस ट्रांजैक्शन में ई-इनवॉइसिंग की व्यवस्था 1 अक्टूबर से लागू की गई थी। 500 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए इसे अनिवार्य बनाया गया था।

गल्फ ऑयल का शुद्ध लाभ दूसरी तिमाही में 4.59 प्रतिशत गिरा

मुंबई। एजेंसी

हिंदुजा समूह की कंपनी गल्फ ऑयल का शुद्ध लाभ जुलाई-सितंबर तिमाही में 4.59 प्रतिशत गिर गया। इस दौरान यह 59.13 करोड़ रुपये रहा। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी को 61.98 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था। कंपनी ने शनिवार को एक बयान में कहा कि समीक्षावधि में उसकी शुद्ध बिक्री दो प्रतिशत गिरकर 411.74 करोड़ रुपये रही। पिछले साल यह इसी अवधि में 421.28 करोड़ रुपये थी। गल्फ ऑयल के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि चावला ने कहा, "विभिन्न श्रेणियों में मांग सुधर रही है। हमें खुशी है कि कारोबार और मुनाफे दोनों की दृष्टि से इस तिमाही में हमारा प्रदर्शन बेहतर रहा है।" गल्फ ऑयल, इंजन ऑयल एवं लुब्रिकेंट्स का कारोबार करती है।

जीएसटीएन ने एक साथ तीन लाख उपयोगकर्ताओं को संभालने के लिए बुनियादी ढांचे को उन्नत किया

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

जीएसटीएन ने रविवार को कहा कि जीएसटी नेटवर्क के बुनियादी ढांचे को उन्नत बनाया गया है, ताकि एक साथ तीन लाख उपयोगकर्ताओं को संभाला जा सके। वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) ने कहा कि इसके अलावा स्वतः निकासी वाले बिक्री फॉर्म जीएसटीआर-3बी को पीडीएफ के रूप में पेश किया गया है, जो अक्टूबर 2020 की कर अवधि और उसके बाद से उपलब्ध होगा। जीएसटीएन ने एक बयान में कहा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट की स्वतः निकासी के साथ पीडीएफ साझा पोर्टल (जीएसटीएन) पर 12 नवंबर 2020 से उपलब्ध होगा। जीएसटीएन ने कहा कि उसने गेटवे (एक साथ उपयोगकर्ताओं की संख्या) की क्षमता को 1.5 लाख से बढ़ाकर तीन लाख कर दिया है। बयान में कहा गया कि

लॉकडाउन में राहत के बाद अप्रत्यक्ष कर गतिविधियों में करदाताओं की संख्या तेजी से बढ़ने की उम्मीद के चलते ऐसा किया गया है। बयान में आगे कहा गया कि जरूरत पड़ने पर इस क्षमता को पांच लाख तक बढ़ाया जा सकता है।

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने लॉन्च किया 'नर्चरिंग नेबरहुड्स चैलेंज'

स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत शिशुओं और छोटे बच्चों के विकास के लिए पड़ोस में बेहतर और मित्रतापूर्ण माहौल बनाने का प्रयास

नई दिल्ली। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के स्मार्ट सिटीज मिशन ने नीदरलैंड स्थित बर्नाड वैन लीयर फाउंडेशन (ँन्ध्) के सहयोग में 'नर्चरिंग नेबरहुड्स चैलेंज' के लिए एक शुरुआती कार्यक्रम का आयोजन किया। इसे डब्ल्यूआरआई इंडिया का तकनीकी सहयोग मिला। इस पहल के तहत सार्वजनिक क्षेत्र में 0-5 वर्ष के शिशुओं और छोटे बच्चों और उनका पालन पोषण करने वाले लोगों की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित किया गया। यह पहल भारतीय शहरों के स्थिर गति से समग्र विकास और शहरों में परिवारों के लिए मित्रतापूर्ण माहौल विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह प्रोग्राम देशभर में होने वाले चैलेंज को समर्थन देगा। इस चैलेंज के लिए 4 नवंबर 2020 से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सभी स्मार्ट सिटीज, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी और 5 लाख से अधिक की आबादी वाले शहर इस पहल में भागीदारी के योग्य हैं।

सबका साथ, सबका विकास के अपने मुख्य लक्ष्य के तहत भारत सरकार शहरी क्षेत्रों में समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित सभी लोगों, खासतौर से शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए सुविधाएं और विकास के अवसरों में बढ़ोतरी के लिए प्रतिबद्ध है। नर्चरिंग नेबरहुड्स चैलेंज से भारतीय शहरों से सार्वजनिक क्षेत्र में सुविधाएं बढ़ाने, आवागमन के साधनों में सुधार और सेवाओं तक सभी की पहुंच बढ़ाने के साथ आंकड़ों के प्रबंधन के लिए प्रस्ताव देने और बच्चों और उनके पैरेंट्स को घरों के आसपास स्वास्थ्य और रहनसहन की सुविधाओं के सुधार करने की खुली अपील की गई। यह पहल नवजात शिशुओं, छोटे बच्चों और उनकी देखभाल करने वाले लोगों की शारीरिक और मानसिक सेहत को और दुरुस्त बनाएगी।

रिसर्च से पता चलता है कि शिशुओं और छोटे बच्चों की बेहतर देखभाल बढ़ती उम्र में बच्चों के संपूर्ण विकास और उनके पूरी क्षमता विकसित करने के लिए बहुत आवश्यक है। कोरोना वायरस के प्रकोप ने शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए उनके घरों के आसपास कुदरती रूप से हरे-भरे क्षेत्रों और जरूरी सेवाएं देने के साथ उन्हें खेलने के अवसर उपलब्ध कराने की अहमियत को उभारा है। गर्भवती महिलाओं, छोटे बच्चों और उनके परिवारों को दी जाने वाली सुविधाओं में सुधार कर शहर मजबूत समुदाय, आर्थिक विकास और सभी के लिए बेहतर माहौल को बढ़ावा दे सकते हैं। नर्चरिंग नेबरहुड्स चैलेंज के माध्यम से शहरों को पार्क-बाग-बगीचों और खुली जगह बनाने पर दोबारा विचार करने के लिए आमंत्रित किया गया है।

बर्नार्ड वान लीयर फाउंडेशन में भारत की प्रतिनिधि रुश्दा मजीद ने कहा, 'हमारा विश्वास है कि नवजात शिशुओं, छोटे बच्चों, पैरेंट्स और बच्चों का पालन-पोषण करने वाले दूसरे लोगों को पड़ोस में बेहतर और अच्छा माहौल उपलब्ध कराना शहरों के संपूर्ण विकास के संबंध में विचार करने का स्थिर और समावेशी तरीका है। शहरों के विकास का आधार शानदार आधारपूर्ण ढांचे और छोटे बच्चों समेत सभी लोगों को बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध कराना होना चाहिए। सार्वजनिक जगहों, आवागमन के साधनों, बच्चों के लिए जरूरी सुविधाओं तक पहुंच बनाने और छोटे बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण की दिशा में समान पहलुओं पर भी ध्यान देना चाहिए। नवजात शिशुओं को बेहतर सुविधाएं देने वाले शहरों के सभी नागरिकों के कल्याण के लिए बेहतर कार्य करने की संभावना होती है। हम इस महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत के लिए स्वास्थ्य और शहरी मामलों के मंत्रालय के बेहद आभारी हैं। हम इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टिट्यूट इंडिया और भागीदारी करने वाले शहरों की साझेदारी में काम करेंगे।

बैंक सभी खातों को अगले साल मार्च तक आधार से जोड़ें-वित्तमंत्री

मुंबई। एजेंसी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बैंकों से 31 मार्च, 2021 तक सभी खातों को संबंधित ग्राहकों की आधार संख्या से जोड़ने का काम सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेश की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। अभी इसे आगे बढ़ाना बाकी है। कई ऐसे खाते हैं, जो अबतक आधार से नहीं जुड़े हैं। भारतीय बैंक संघ (आईबीए) की 73वीं सालाना आम बैठक के संबोधित करते हुए सीतारमण ने कहा, ''प्रत्येक खाता 31 मार्च, 2021 तक आधार से जुड़ना चाहिए और जहां भी जरूरी तथा लागू हो, पैन से उसे जोड़ा जाना चाहिए।'' उन्होंने यह भी कहा कि बैंकों को डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित और अन्य रूप से किये जाने को वाले भुगतान को हतोत्साहित करना चाहिए। उन्होंने यूपीआई आधारित भुगतान को अपनाने पर भी जोर दिया। वित्त मंत्री ने कहा, ''यूपीआई हमारे सभी बैंकों में आम बोलचाल के शब्द होने चाहिए।'' उन्होंने रूपे कार्ड को भी बढ़ावा देने पर जोर दिया। सीतरमण ने कहा, ''जिसे भी कार्ड की जरूरत है, आप उहें केवल रूपे कार्ड ही जारी करें।'' उन्होंने कहा कि देश बड़े आकार के बैंकों पर जोर दे रहा है।

उद्योग परिसंघ नवाचारों और अनुसंधानों की पहचान कर उन्हें आगे लाएं: मिश्र

जयपुर। एजेंसी

राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने उद्योगों से अनुसंधान और डिजाइन के नवाचारों को प्रोत्साहित करने वाली संस्थागत प्रणाली विकसित करने का आह्वान किया है। उन्होंने भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) को राज्यों में नवीनतम अनुसंधान और डिज़ाइन पेटेंट कराने के लिए उद्यमियों को प्रेरित करने की नीति पर कार्य करने पर जोर दिया। उन्होंने 'शिक्षित अर्थव्यवस्था' की सोच के साथ काम करने पर जोर देते हुए कहा कि औद्योगिक विकास के लिए सरकार और उद्यमियों की साझा समझ विकसित किये जाने से ही देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ सकती है। मिश्र आज यहां भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा 'अनुसंधान विकास एवं नवाचारों के जरिये औद्योगिक विकास' विषयक राष्ट्रीय सम्मेलन को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नवाचार अपनाते हुए उच्च विकास वृद्धि की रणनीति पर कार्य करना आज समय की जरूरत है। इसके लिए छोटे छोटे स्थानों पर होने वाले लोकल नवाचारों, डिज़ायन के नवीनतम रूपों और अनुसंधानों की पहचान कर उन्हें आगे लाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि देश में क्षमताओं की कमी नहीं है, पर एक राष्ट्रीय अनुसंधान और नवाचार प्रणाली के आवश्यक घटकों के विकास में औद्योगिक क्षेत्रों को आगे आकर कार्य करने की जरूरत है। मिश्र ने भारत सरकार द्वारा देशभर के राज्यों में पेटेंट सूचना केन्द्रों, प्रौद्योगिकी और नवाचार सहायता केंद्रों के लिए किए गये प्रयासों की चर्चा करते हुए कहा कि इनमें उपलब्ध अवसरों के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहित करने में उद्योग परिसंघ जैसी संस्थाएं अपना योगदान दें। राज्यपाल ने नई शिक्षा नीति की चर्चा करते हुए कहा कि इसमें व्यावसायिक दक्षता पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने अनुसंधान और नवाचारों के लिए देश में प्रभावी वातावरण बनाए जाने पर भी जोर दिया।

ईएसआईसी से बेरोजगारी लाभ का दावा करने के लिए हलफनामे की जरूरत नहीं

नयी दिल्ली। एजेंसी

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने बेरोजगारी लाभ का दावा करने के लिए शर्तों में छूट दी है और दावाकर्ताओं को अब इसके लिए हलफनामा दाखिल करने की जरूरत नहीं। श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अब ईएसआईसी की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (एबीवीकेवाई) के तहत हलफनामे के जरिए दावा करने की जरूरत नहीं होगी। इन दावों को जरूरी दस्तावेजों की स्कैन प्रतियों के साथ ऑनलाइन दाखिल किया जा सकेगा। ईएसआईसी ने 20 अगस्त 2020 को हुई अपनी बैठक में अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना योजना को एक जुलाई 2020 से बढ़ाकर 30 जून 2021 तक कर दिया था। इस योजना के तहत दी जाने वाली राहत दर को औसत दैनिक आय के 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने का निर्णय भी लिया गया और साथ ही 24 मार्च 2020 से 31 दिसंबर 2020 की अवधि के लिए पात्रता शर्तों में भी छूट दी गई। सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान बेरोजगार हुए श्रमिको को राहत पहुंचाने के लिए यह फैसला किया।

LTC scheme
सरकारी कर्मचारियों के परिवार सदस्य के नाम भी हो सकती है खरीदारी

नई दिल्ली। एजेंसी

केंद्र सरकार के कर्मचारी एलटीसी कैश वाउचर योजना (LTC Cash Voucher Scheme) के तहत पत्नी या परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से वस्तुओं या सेवाओं की खरीदारी कर सकते हैं। हालांकि, ये सदस्य एलटीसी किराया पाने के योग्य होने चाहिए। 12 फीसदी से ज्यादा जीएसटी वाले सामान खरीद सकते हैं। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने इस योजना के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले सवालों (एफएक्यू) के जवाब में स्पष्ट किया कि यदि किसी कर्मचारी ने औपचारिक रूप से इस योजना में शामिल होने का विकल्प नहीं चुना है, तो भी वह 12 अक्टूबर या इसके बाद 12 प्रतिशत से अधिक जीएसटी वाली वस्तुओं या सेवाओं की खरीदपर धनराशि पाने का दावा कर सकता है।

इस फेस्टिव सीजन में ऑनलाइन रीटेल ने रेकॉर्ड बिक्री की। दशहरा पर आयोजित फेस्टिव सेल में शुरुआती चार दिनों मे ऐमजॉन और फ्लिपकार्ट ने करीब 29000 करोड़ रुपये की बिक्री की। दिवाली से पहले जियोमार्ट पर सेल का आयोजन किया गया है। यहां फेस्टिव प्रॉडक्ट पर 50 फीसदी तक की छूट ऑफर की जा रही है।

पत्नी और परिवार के सदस्य कर सकते हैं खरीदारी

व्यय विभाग ने कहा, 'योजना के तहत खरीदे गए सामान और सेवाओं के चालान पति या पत्नी या किसी अन्य पारिवारिक सदस्य के नाम पर हो सकता है, जो एलटीसी के लिए पात्र हैं।' सरकार ने अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ावा देने के लिए इस साल अपने कर्मचारियों को अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) के एवज में नकद वाउचर देने की घोषणा की है। इन वाउचर का इस्तेमाल सिर्फ ऐसे गैर-खाद्य सामान खरीदने के लिए किया जा सकता है जिनपर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लगता है। कर्मचारी उन वाउचर का इस्तेमाल ऐसे उत्पाद खरीदने के लिए कर सकते हैं जिन पर जीएसटी की दर 12 प्रतिशत या अधिक है।

RBI के आंकड़ों से अच्छे संकेत!

अक्टूबर 2020 में बैंकों के कर्ज और डिपॉजिट में हुई बढ़ोतरी

नई दिल्ली। एजेंसी

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के कोरोना संकट के बीच बैंकों की ओर से बांटे गए कर्ज (Credits) और ग्राहकों की ओर से किए गए डिपॉजिट (Deposits) में वृद्धि को लेकर जारी किए गए आंकड़े देश की अर्थव्यवस्था (Indian Economy) के लिए अच्छे संकेत माने जा रहे हैं। आरबीआई डाटा के मुताबिक, 23 अक्टूबर को खत्म हुए पखवाड़े (Fortnight) के दौरान बैंकों के लोन पोर्टफोलियो में 5.06 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। इससे बैंकों का कर्ज 103.39 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। इस दौरान बैंकों का जमा 10.12 फीसदी बढ़कर 142.92 करोड़ रुपये हो गया है।

9 अक्टूबर को खत्म पखवाड़े के मुकाबले कम हुई बढ़ोतरी

रिजर्व बैंक की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, 9 अक्टूबर 2020 को समाप्त पखवाड़े के दौरान बैंकों के कर्ज में 5.66 और जमा में 10.55 फीसदी बढ़ोतरी दर्ज की गई थी यानी 23 अक्टूबर 2020 को खत्म पखवाड़े में दोनों में हुई वृद्धि इसके मुकाबले कुछ कम है। आंकड़ों के अनुसार, 25 अक्टूबर 2019 को खत्म हुए पखवाड़े में बैंकों का कर्ज 98.40 लाख करोड़ रुपये था. वहीं, जमा राशि 129.73 लाख करोड़ रुपये थी। सितंबर 2020 में नॉन-फूड बैंक क्रेडिट ग्रोथ घटकर 5.8 फीसदी रही, जो पिछले साल के इसी महीने में 8.1 फीसदी थी।

केंद्रीय बैंक के मुताबिक, सितंबर 2020 में इंडस्ट्रीज को बांटे गए कर्ज (Industry Credit) में कोई बढ़ोतरी दर्ज नहीं हुई है यानी इस सेक्टर में कर्ज वृद्धि शून्य रही है। वहीं, सितंबर 2019 के दौरान इंडस्ट्रीज को बांटे गए कर्ज में 2.7 फीसदी बढ़ोतरी हुई थी। सितंबर 2020 में सर्विस सेक्टर (एीन्म एाूर्द्दे) में कर्ज वृद्धि दर 9.1 फीसदी रही, जो पिछले साल इसी महीने में 7.3 फीसदी थी। सितंबर 2019 में 16.6 फीसदी की बढ़ोतरी के मुकाबले पर्सनल लोन में इस सितंबर 2020 के दौरान सिर्फ में 9.2 फीसदी बढ़ोतरी ही दर्ज की गई है।

माइंड वार्स का पूरे भारत में स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों के लिए

भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन जीके ओलिम्पयाड लॉन्च किय

नई दिल्ली। एजेंसी

एजेंसी जीके शब्द का सामान्य बुद्धिमता से गहरा नाता है, यह हमारे जीवन में घटित होने वाली चीजों के महत्व के प्रति हमारी समझ को दर्शाता है। ओलिम्पयाड जैसे टेस्ट में हिस्सा लेने पर विद्यार्थी क्विज एवं पजल के माध्यम से सीखते हैं, और इससे वह अपने जीवन में अधिक निर्णायक तथा आत्मविश्वास से परिपूर्ण बन पाते हैं। प्रत्येक माता-पिता की यह इच्छा होती है कि उनके बच्चे बच्चे में चाहे जो भी करें, उसमें वह सफलता हासिल करें और नए मुकाम बनाएं, माइंड वार्स उनकी इसी इच्छा को पूरा करने आया है; माइंड वार्स एक मल्टीप्लेटफॉर्म नॉलेज प्रोग्राम है, इसे जी इंटरटेनमेन्ट इंटरप्राइजेज लिमिटेड ने प्रमोट किया है, यह भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन सामान्य ज्ञान ओलिम्पयाड 2020 है,इसका उद्देश्य है कि एक बेहतर भविष्य के सृजन हेतु विद्यार्थियों की पहचान की जाए, उन्हें प्रोत्साहित किया जाए और उन्हें बढ़ावा दिया जाए। नवम्बर 2020 में एक राष्ट्रीय-स्तर की चैम्पियनशिप आरम्भ होगी, और यह समग्र भारत के सभी शिक्षा बोर्ड के कक्षा 4 से 12 के विद्यार्थियों के लिए रहेगी। इसमें 20 मिनट की परीक्षा होगी, जिसमें प्रत्येक कक्षा के 5 विषयों में से सुसंगत एवं रोचक सम-सामायिकी के प्रश्न शामिल होंगे, इनका उद्देश्य होगा कि आने वाले वर्षों में विद्यार्थियों की क्षमता एवं वृद्धि को बेहतर बनाया जाए। इसके अलावा इसे पूरे भारत में लगभग 5,000 भारतीय विद्यालयों के प्रधानाचार्यों एवं शिक्षकों के साथ किए गए एक व्यापक सर्वेक्षण से प्राप्त परिणाम के आधार पर सूचीकृत किया गया है। विद्यार्थीगण ऑनलाइन ओलिम्पयाड के लिएकिसी बाधा के बिना 24X7 अभ्यास भी कर सकते हैं, और इसमें उनके पास राष्ट्रीय चैम्पियन के रूप में सम्मान पाने और रु 1 करोड़ का पुरस्कार पाने का अवसर भी रहेगा।

टाटा स्काय बिंज ने अपनी व्यापक कंटेंट लाइब्रेरी को किया विस्तारित

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

टाटास्काय की ओटीटी एग्रीगेटर सर्विस, टाटास्काय बिंज ने त्योहारों के इस सीज़न उपभोक्ताओं को उत्कृष्ट सेवाए प्रदान करने के लिए सोनी लिव के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी के तहत टाटास्काय बिंज पर 1000 घण्टे का रोचक कंटेंट शामिल हो जाएगा जिसमें टीवी शोज, फिल्में और सोनी लिव ओरिजिनल्स जैसे स्कैम 1992- द हर्षद मेहता स्टोरी, जेएल 50, अवरोध- द सीज़ विदिन, यॉरऑनर, अनदेखी तथा फिल्में जेसेकदख, राम सिंह चार्ली आदि शामिल होंगे। यह सोनी पिक्चर्स नेटवर्क के चैनलों से फिल्में, और टीवी शोज पेश करेगा और साथ ही साथ लाईव स्पोर्ट्स भी दिखेगा।

इस साझेदारी पर बात करते हुए पल्लव पुरी, चीफ़ कमर्शियल एण्ड कंटेंट आफिसर, टाटा स्काय ने कहा, "हम हमेशा से कंटेंट में नई पेशकश के साथ अपने उपभोक्ताओं को उत्कृष्ट अनुभव प्रदान करते रहे हैं। एक समान दृष्टिकोण होने के नाते, हमें वि'वास है कि सोनी लिव के बेहतरीन कंटेंट से युक्त लाइब्रेरी हमारे सब्सक्राइबरों को टाटा स्काय बिंज प्लेटफॉर्म पर रोचक एवं मनोरंजक कंटेंट उपलब्ध कराती रहेगी।" इस साझेदारी पर बात करते हुए डेनिश खान, बिज़नेस हैड-सोनी एंटरटेनमेन्ट टेलीविज़न, डिजिटल बिजनेस एण्ड स्टुडियो नेक्स्ट ने कहा, "रीलॉन्च से लेकर अब तक बड़े स्क्रीन पर हमारे कंटेंट की खपत तथा कनेक्टेड डिवाइसेज़ में लगातार बढ़ोतरी हुई है और टाटास्काय बिंज के साथ हमारी यह साझेदारी बड़े स्क्रीन वाले परिवारों में हमें और भी अग्रणी स्थिति पर स्थापित करेगी। हमारे पास कंटेंट की व्यापक लाइब्रेरी है जो टाटास्काय बिंज के उपयोगकर्ताओं को ढेरों विकल्प उपलब्ध कराएगी। इस साझेदारी के माध्यम से हम ऐसे समय में अपने आपको और मजबूत बना सकेंगे, जब उपभोक्ता रोचक कहानियों के लिए अपने स्क्रीन्स के साथ निरंतर जुड़े हुए हैं। हमें खुशी है दोनों ब्राण्ड्स के साथ हमारा रिश्ता और मजबूत होता जा रहा है।"

दिवाली के मौके पर अपनों को बादाम की सौगात देकर अपना प्यार जताएं

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

त्योहारों का मौसम परवान चढ़ने के साथ-साथ दिवाली भी करीब आ पहुंची है। ऐसे में आपके कामों की लिस्टर उतनी ही लंबी होगी जितनी आपकी सामाजिक प्रतिबद्धताएँ। घर की सजावट और त्योहारों के व्यंजन बनाने से लेकर, सबसे खास पूजा की थाली ढूंढ़ने या अपने परिवार और दोस्तों के लिए परफेक्ट उपहार तय करने तक, ऐसी कई चीज़ें हैं जिन पर आपका ध्यान दिया जाना ज़रूरी है। हालांकि अब तक जारी महामारी के कारण इस साल का जश्न उतना भव्य नहीं होगा, लेकिन फिर भी परिवार के साथ खुशियाँ और प्यार साझा करने के लिए दिवाली एक महत्वपूर्ण क्षण है।

इस साल तंदुरुस्ती और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित रहने के कारण इस अप्रत्याशित समय में अपने प्रियजनों से सेहत बढ़ाने वाले उपहारों

को साझा कर सकते हैं। इससे दीपावली के अवसर पर उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देने का एक मौका आपको मिल सकता है। उपहार के नियमित और रूटीन विकल्पों की जगह हाथों से बने दीए या मोमबत्ती, सजावट की वस्तुएँ या रिसाइकल किए गए उत्पादों से बने कपड़े या बादाम जैसे सेहतमंद और पोषणयुक्त आहार के बारे में विचार करें। बादाम को अच्छी सेहत का उपहार भी कहा जाता है क्योंकि इससे हृदय की सेहत, डायबिटीज़ और वज़न प्रबंधन में विभिन्न प्रकार के लाभ मिलते हैं। इसके अलावा बादाम से कॉपर, ज़िंक, फॉलेट, आयरन (लोह) और विटामिन ई प्राप्त होते हैं–ये सभी रोग प्रतिरोधक प्रणाली को मदद करते हैं। ये सारे गुण बादाम को घर पर रखने के लिए सबसे अच्छा आहार बनाते हैं, खास तौर पर जब परिवार की प्राथमिकता रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना हो।

तो इस साल परिवार के बीच समय बिताने के साथ नियमित आनंदोत्सव सहित एक सुरक्षित और सेहतमंद दीपावली मनाएँ। पटाखों से दूर रहें, अच्छे चमकीले दीए जलाएँ, दीए सजाएँ, आपके दिलों और घरों में देवी लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए रंगोली बनाएँ, लेकिन यह सब करें सेहतमंद आहार पर ध्यान केंद्रित करते हुए और सोशल डिस्टेन्सिंग बनाकर रखते हुए।

इस त्योहार के मौसम में अपने प्रियजनों की सेहत का ख्या ल रखने के महत्व के बारे में बात करते हुए बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा सोहा अली खान ने कहा, 'त्यो हारों के मौसम में, हम लोगों में से कइ लोगों के लिए जश्न में बह जाना और अपनी सेहत की ओर से लापरवाह हो जाना बहुत आसान है। इसलिए, इस दीपावली में अपने करीबी और

प्रियजनों को क्या उपहार दूँगी इसे लेकर मैं ज़्यादा सावधानी बरतूंगी। मेरी उपहार की सूची में पहली चीज़ है बादाम क्योंकि इसमें विटामिन बी2, फॉस्फोरस, मैग्नी शियम, प्रोटीन इत्यादि सहित विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जो एक सेहतमंद जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण हैं। कई लोगों को यह नहीं पता है बादाम अनेक ऐसे पोषक तत्व उपलब्ध कराता है जो रोग इम्युकनिटी को मजबूती देने के लिए जाने जाते हैं- एक और कारण है जिससे आप बादाम उपहार के तौर पर देकर अच्छा महसूस कर सकते हैं।'

17 साल बाद सर्वार्थसिद्धि योग में दिवाली

गृहस्थों और व्यापारियों के लिए लक्ष्मी पूजन शुभ मुहूर्त

हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष कार्तिक माह के कृष्णपक्ष की अमावस्या तिथि पर दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। इस वर्ष दिवाली शनिवार, 14 नवंबर के दिन मनाई जा रही है। कई वर्षों के बाद शनिवार के दिन दिवाली मनाई जाएगी जो एक दुर्लभ संयोग है। अगर ग्रहों की चाल के बात करें तो ज्योतिषाचार्यों के अनुसार शनिवार को शनि स्वयं की राशि में होने से दिवाली बहुत ही शुभ लाभकारी होगी। 17 साल के बाद सर्वार्थ सिद्धि योग में दिवाली पूजन और उत्सव मनाया जाएगा। दिवाली पर भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की विधिवत रूप से पूजा करने की परंपरा होती है। आइए जानते हैं इस दिवाली लक्ष्मी-गणेश पूजन करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा।

दिवाली 2020 लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त

■ **लक्ष्मी पूजा मुहूर्त्त, 14 नवंबर :** शाम 5 बजकर 30 मिनट से 7 बजकर 25 मिनट तक

अवधि : 1 घंटे 55 मिनट

प्रदोष काल : शाम 5:27 मिनट से 8:06 मिनट तक

वृषभ काल : 14 नवंबर शाम 5:30 मिनट से 7:25 मिनट तक

■ **लक्ष्मी पूजन 2020:** चौघड़िया मुहूर्त

दोपहर का समय: 2:18 से शाम 4 बजकर 7 मिनट तक

शाम: शाम को 5:30 मिनट से शाम 7 बजकर 8 मिनट तक

रात्रि: रात 8: 50 मिनट से देर रात 1 बजकर 45 मिनट तक

प्रात:काल: 15 नवंबर को सुबह 5:04 मिनट से 6:44 मिनट तक

दिवाली महानिशीथ काल मुहूर्त

■ **लक्ष्मी पूजा मुहूर्त्त :** 23:39 मिनट से 24:32 मिनट तक

गृहस्थों के लिए लक्ष्मी पूजा 2020 मुहूर्त

प्रदोष काल मुहूर्त, 14 नवंबर: शाम 5 बजकर 33 मिनट से रात को 8 बजकर 12 मिनट तक

वृषभ काल मुहूर्त, 14 नवंबर: शाम 5 बजकर 30 मिनट से रात के 7 बजकर 25 मिनट तक

सिंह लग्न मुहूर्त, 14 नवंबर: आधी रात 12 बजकर 05 मिनट से देर रात 2:20 बजकर मिनट तक

सर्वश्रेष्ठ पूजा मुहूर्त: शाम 5:30 मिनट से 6:02 मिनट तक

व्यापारियों के लिए लक्ष्मी पूजा मुहूर्त

■ **सर्वश्रेष्ठ अभिजीत मुहूर्त:** दोपहर 12:09 मिनट से शाम को 4:05 मिनट तक

यक्ष, गंधर्व और देवों का त्योहार है दीपावली

करते हैं इस दिन साधना

भारतवर्ष में प्राचीनकाल में देव, दैत्य, दानव, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग, विद्याधर आदि अनेक प्रकार की जाति हुआ करती थी। सभी के पर्व और त्योहार अलग अलग थे परंतु कुछ त्योहार कामन भी थे। जैसे वर्तमान में भारत के हर प्रांत में अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं उदाहरणार्थ छट पर्व उत्तर भारत का त्योहार है दक्षिण भारत में इसका कोई खास महत्व नहीं है। उसी तरह प्राचीन काल की जातियों के त्योहार भी भिन्न होते थे। ऐसी मान्यता है कि उन्हीं में से एक यक्ष जाति भी थी जो कई तरह के उत्सव मनानी थी।

यक्षों का त्योहार : कहते हैं कि दीपावली यक्ष नाम की जाति के लोगों का ही उत्सव था। उनके साथ गंधर्व भी यह उत्सव मनाते थे। मान्यता है कि दीपावली की रात्रि को यक्ष अपने राजा कुबेर के साथ हास-विलास में बिताते व अपनी यक्षिणियों के साथ आमोद-प्रमोद करते थे। सभ्यता के विकास के साथ यह त्योहार मानवीय हो गया और धन के देवता कुबेर की बजाय धन की देवी लक्ष्मी की इस अवसर पर पूजा होने लगी, क्योंकि कुबेर जी की मान्यता सिर्फ यक्ष जातियों में थी पर लक्ष्मीजी की देव तथा मानव जातियों में। कई जगहों पर अभी भी दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजा के साथ-साथ कुबेर की भी पूजा होती है।

बिरंगी आतिशबाजी, स्वादिष्ट पकवान एवं मनोरंजन के जो विविध कार्यक्रम होते हैं, वे यक्षों की ही देन हैं। कहते हैं कि लक्ष्मी, कुबेर के साथ गणेशजी की पूजा का प्रचलन भौव-सम्प्रदाय के लोगों ने किया। ऋद्धि-सिद्धि के दाता के रूप में उन्होंने गणेशजी को प्रतिष्ठित किया। यदि तार्किक आधार पर देखें तो कुबेर जी मात्र धन के अधिपति हैं जबकि गणेश जी संपूर्ण ऋद्धि-सिद्धि के दाता माने जाते हैं। इसी प्रकार लक्ष्मी जी मात्र धन की स्वामिनी नहीं वरन ऐश्वर्य एवं सुख-समृद्धि की भी स्वामिनी मानी जाती हैं। अतः कालांतर में लक्ष्मी-गणेश का संबध लक्ष्मी-कुबेर की बजाय अधिक निकट प्रतीत होने लगा। दीपावली के साथ लक्ष्मी पूजन के जुड़ने का कारण लक्ष्मी और विष्णुजी का इसी दिन विवाह सम्पन्न होना भी माना गया है।

देवों का त्योहार : कहते हैं कि दीपावली का पर्व सबसे पहले राजा महाबली के काल से प्रारंभ हुआ था। विष्णु ने तीन पग में तीनों लोकों को नाप लिया। राजा बली की दानशीलता से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल लोक का राज्य दे दिया, साथ ही यह भी आश्वासन दिया कि उनकी याद में भू लोकवासी प्रत्येक वर्ष दीपावली मनाएंगे। तभी से दीपोत्सव का पर्व प्रारंभ हुआ। यह भी कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने राजा बली को पाताल लोक का स्वामी बनाया था और इन्द्र ने स्वर्ग को सुरक्षित जानकर प्रसन्नतापूर्वक दीपावली मनाई थी।

नरक चतुर्दशी को छोटी दिवाली, अमावस्या को बड़ी दीपावली के बाद कार्तिक पूर्णीमा को देव दिवाली होती है। यह दिवाली देवता मनाते हैं। मान्यताओं के अनुसार देव दीपावली के दिन सभी देवता गंगा नदी के घाट पर आकर दीप जलाकर अपनी प्रसन्नता को दर्शाते हैं।

मनुष्यों का त्योहार भी : इस दिन भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक का स्वामी बनाया था इसलिए दक्षिण भारत के लोगों के लिए यह महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन के ठीक एक दिन पहले श्रीकृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था। इस खुशी के मौके पर दूसरे दिन दीप जलाए गए थे। यह दिन भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस भी है। गौतम बुद्ध के अनुयायियों ने 2500 वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध के स्वागत में लाखों दीप जला कर दीपावली मनाई थी। एक मान्यता अनुसार इसी दिन भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। इसी दिन समुद्रमंथन के पश्चात लक्ष्मी व धन्वंतरि प्रकट हुए थे। इसी दिन माता काली भी प्रकट हुई थी इसलिए बंगाल में दीपावली के दिन कालिका की पूजा का प्रचलन है।

धनतेरस पर 6 देवों की होती है पूजा

हिन्दू कैलेंडर के अनुसार कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। यह पांच दिन चलने वाले दीपावली उत्सव का पहला दिन होता है। धनतेरस से ही तीन दिन तक चलने वाला गोत्रिरात्र व्रत भी शुरू होता है। इस दिन पांच देवों की पूजा होती है।

1.धन्वंतरि पूजा : हिन्दू मान्यता अनुसार धन तेरस के दिन समुद्र मंथन से आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। अमृत कलश के अमृत का पान करके देवता अमर हो गए थे। इसीलिए आयु और स्वस्थता की कामना हेतु धनतेरस पर भगवान धन्वंतरि का पूजन किया जाता है।

2.लक्ष्मी पूजा : इस दिन लक्ष्मी पूजा का भी महत्व है। श्रीसूक्त में वर्णन है कि लक्ष्मीजी भय और शोक से मुक्ति दिलाती हैं तथा धन-धान्य और अन्य सुविधाओं से युक्त करके मनुष्य को निरोगी काया और लंबी आयु देती हैं।

3.कुबेर पूजा : धन के देवता कुबेर की इस दिन विशेष पूजा होती है। कुबेर भी आसुरी प्रवृत्तियों का हरण करने वाले देव हैं इसीलिए उनकी भी पूजा का प्रचलन है।

4.यम पूजा : धन तेरस के दिन यम पूजा का भी महत्व है। कहते हैं कि धनतेरस के दिन यमराज के निमित्त जहां दीपदान किया जाता है, वहां अकाल मृत्यु नहीं होती है।

5.गणेश पूजा : गणेशजी की पूजा प्रत्येक मांगलिक कार्य और त्योहार में की जाती है क्योंकि वे प्रथम पूज्य हैं। सभी के साथ गणेश पूजा की जाना जरूरी होती है।

6.पशु पूजा : धनतेरस के दिन ग्रामीण क्षेत्र में मवेशियों को अच्छे से सजाकर उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि ग्रामीणों के लिए पशु धन का सबसे ज्यादा महत्व होता है। दक्षिण भारत में लोग गायों को देवी लक्ष्मी के अवतार के रूप में मानते हैं इसलिए वहां के लोग गाय का विशेष सम्मान और आदर करते हैं।

अब सस्ता होना शुरू होगा प्याज, इसे लेकर एक बड़ा आदेश हुआ है जारी!

नई दिल्ली। एजेंसी

सहकारी संस्था नेफेड ने कहा कि उसने 15,000 टन आयातित प्याज की आपूर्ति के लिए आदेश जारी किए हैं और इस संबंध में बोलीदाताओं को अंतिम रूप दे दिया गया है। नेफेड ने कहा कि इससे घरेलू बाजार में उपलब्धता बढ़ेगी और कीमतें काबू में रहेंगी। नेफेड ने आगे कहा कि आयातित प्याज बंदरगाह शहरों से वितरित किया जाएगा, इसलिए तेजी से आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों से पूछा गया है कि उन्हें कितनी मात्रा में प्याज चाहिए। नेफेड ने आयातित प्याज की अतिरिक्त आपूर्ति के लिए नियमित निविदा जारी करने की योजना बनाई है। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, नेफेड को तूतीकोरिन और मुंबई में आपूर्ति के लिए जारी निविदाओं के लिए अच्छी प्रतिक्रिया मिली। नेफेड ने कल शाम ही सफल बोलीदाताओं को अंतिम रूप दे दिया, ताकि बाजार में समय पर आपूर्ति हो सके।'' नेफेड ने कहा कि इस बार उसने प्याज की गुणवत्ता और आकार पर खासतौर से जोर दिया है, जो भारतीय उपभोक्ताओं की पसंद से मेल खाता हो। गौरतलब है कि भारत में आमतौर पर मध्यम आकार के प्याज को पसंद किया जाता है, जबकि विदेशी प्याज आकार में 80 मिमी तक बड़े होते हैं।

पिछले साल एमएमटीसी ने तुर्की और मिस्र से सीधे पीले, गुलाबी और लाल प्याज का आयात किया था, जबकि इस साल कम से कम समय में अच्छी गुणवत्ता वाले प्याज की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निजी आयातकों को आपूर्ति करने की पेशकश की गई है। नेफेड ने कहा कि इस बीच प्याज की थोक और खुदरा कीमतों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान और अन्य राज्यों से रबी (सर्दी) के पुराने स्टॉक और खरीफ (गर्मी) के नए स्टॉक की आवक से प्याज की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगा है। नेफेड ने उम्मीद जताई कि सरकार के नीतिगत हस्तक्षेप और बफर, आयात तथा नई आवक से आपूर्ति में तेजी होगी और प्याज का बाजार जल्द ही सामान्य हो जाएगा। मंडी भाव के अनुसार देश के कुछ हिस्सों में प्याज की खुदरा कीमतें 80-100 रुपये प्रति किलोग्राम तक हैं।

पोत परिवहन मंत्रालय का नाम बदला

नई दिल्ली। एजेंसी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल में की गई घोषणा के अनुरूप केंद्र सरकार ने पोत परिवहन मंत्रालय का नाम बदलकर बंदरगाह, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय कर दिया है। मंत्रिमंडल सचिवालय की अधिसूचना के मुताबिक इस मंत्रालय के तहत पोत परिवहन और नौवहन, समुद्री व्यापार के लिए शिक्षण एवं प्रशिक्षण, प्रकाशस्तंभ और प्रकाशपोत, बंदरगाहों, पोत परिवहन और नौवहन का प्रशासन काम करेगा। इसमें राष्ट्रीय जलमार्गों के जरिए यात्रियों एवं माल की आवाजाही भी शामिल है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा हस्ताक्षरित अधिसूचना में कहा गया है कि यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और भारत सरकार (कार्य का आवंटन) नियम, 1961 में संशोधन करके लिया गया था। विभिन्न स्वायत्त निकाय जैसे मुंबई, कोलकाता और अन्य बंदरगाह न्यास, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और भारत के पोत परिवहन निगम भी मंत्रालय के अंतर्गत आएंगे। मोदी ने रविवार को गुजरात के घोघा और हजीरा के बीच रोपैक्स फेरी सेवा के शुभारंभ के मौके पर कहा था कि पोत परिवहन मंत्रालय का विस्तार किया जा रहा है और अब इसका नाम बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय होगा। इसी के मुताबिक अब सरकार ने मंत्रालय का नाम बदल दिया है।

भारत के लिए चीनी निर्यात का अच्छा अवसर, निर्यात सब्सिडी इस सत्र में भी जारी रखने की संभावनाः सरकार

नयी दिल्ली। एजेंसी

खाद्य सचिव सुधांशु पाण्डेय ने कहा है कि भारत के पास 2019-20 में नवंबर-अप्रैल के दौरान अंतरराष्ट्रीय बाजार में चीनी बेचने का अच्छा अवसर है। इसकी के मद्देनजर मंत्रालय में एक प्रस्ताव पर विचार चल रहा है कि चीन पर निर्यात सब्सिडी को चालू विपणन सत्र के लिए बढा दिया जाए। वैसे कुछ दिन पहले वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि यह सब्सिडी आगे और जारी रखने का कोई विचार नहीं है। पाण्डेय ने न्यूज एजेंसी से कहा, ''इस साल थाईलैंड में उत्पादन कम होने का अनुमान है, जबकि ब्राजील की पेराई अप्रैल 2021 में शुरू होगी। ऐसे में अब से लेकर अप्रैल तक भारत के लिए निर्यात का अच्छा अवसर है।'' उन्होंने कहा, ''यह एक अवसर है, उद्योग को इसका फायदा उठाना है। भारत को इस साल चीनी का बंपर उत्पादन होने की उम्मीद है और हम इस साल अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं।'' आधिकारिक सूत्रों के अनुसार खाद्य मंत्रालय 60 लाख टन की मौजूदा चीनी निर्यात नीति के सत्र 2020-21 में विस्तार के लिए कैबिनेट की मंजूरी के प्रस्ताव तैयार कर रहा है। सूत्रों ने कहा कि खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने 30 अक्टूबर को कहा था कि सरकार निर्यात सब्सिडी नीति के विस्तार पर विचार नहीं कर रही है, लेकिन हितधारकों और नीति निर्माताओं के साथ कई दौर की बातचीत के बाद अब प्रस्ताव पर नए सिरे से विचार किया जा रहा है। उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि चीनी कीमतें उत्पादन लागत से कम न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए भारत को इस साल 50 लाख टन से अधिक चीनी का निर्यात करने की आवश्यकता है। भारत ने चीनी के अतिरिक्त स्टॉक को कम करने और गन्ना किसानों को भुगतान करने में नकदी संकट से जूझ रहे चीनी मिलों की मदद के लिए पिछले दो वर्षों के दौरान निर्यात सब्सिडी दी थी। जिसकी मियाद सितंबर में समाप्त पिछले सत्र में पूरी हो चुकी है। चीनी मिलों ने आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2019-20 (अक्टूबर-सितंबर) चीनी विपणन सत्र के लिए निर्धारित 60 लाख टन के अनिवार्य कोटा के मुकाबले 57 लाख टन चीनी का निर्यात किया।

रॉयल एनफील्ड की हर तिमाही में एक नई बाइक पेश करने की योजना, अगले सात साल में आएंगे 28 मॉडल

नयी दिल्ली। एजेंसी

प्रमुख मोटरसाइकिल कंपनी रॉयल एनफील्ड की योजना हर तिमाही में एक नई बाइक पेश करने की है और वह अगले सात वर्षों में कम से कम 28 नए मॉडल बाजार में लाएगी। कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि कंपनी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी कर रही है, जिसके तहत यह फैसला किया गया है। इसके अलावा कंपनी थाईलैंड में एक असेंबली इकाई स्थापित करने की योजना भी बना रही है, जिसके बाद ऐसी ही एक इकाई ब्राजील में स्थापित की जाएगी। रॉयल एनफील्ड के सीईओ विनोद के दासारी ने बताया, ''हमने अगले सात वर्षों के लिए एक उत्पाद योजना बनाई है। हम लगभग हर तिमाही में एक नया मॉडल पेश करने जा रहे हैं और मैं वेरिएंट या कलर विकल्प की बात नहीं कर रहा हूं... कम से कम 28 मॉडल, और ये भी न्यूनतम है।'' उन्होंने आगे कहा, ''ये सभी (नए मॉडल) मध्यम खंड में होंगे- 250 सीसी से 750 सीसी तक। हम इस पर ध्यान दे रहे हैं... और हम इसे सभी के लिए उपलब्ध कराएंगे और ये सही मायने में वैश्विक श्रृंखला के अनुरूप होंगे।'' दासारी ने इन नए उत्पादों के लिए किए जाने वाले निवेश पर टिप्पणी नहीं, हालांकि कहा कि नए उत्पादों और नई तकनीक पर कई सौ करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।

अमेरिका की ओर से भारत का जीएसपी दर्जा बहाल कर भेजा जा सकता है मजबूत संकेतः अघी

वाशिंगटन। एजेंसी

अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन और वाशिंगटन द्वारा भारत के मामले में व्यापार से जुड़ी सामान्यीकृत तरजीही प्रणाली (जीएसपी) को बहाल कर देने से ही तुरंत एक छोटा व्यापार समझौता हो सकता है और इससे नयी दिल्ली को एक मजबूत संकेत भी भेजा जा सकता है। एक प्रमुख भारत केन्द्रित अमेरिकी व्यावसायिक पैरवी समूह ने यह कहा है। अमेरिका- भारत रणनीतिक एवं भागीदारी मंच (यूएसआईएसपीएफ) के अध्यक्ष मुकेश अघी ने पीटीआई-भाषा के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि भारत और अमेरिका जल्दी से इस तरह का एक छोटा सा व्यापार समझौता करके आगे बढ़ सकते हैं और आगे बड़े मुद्दों पर ध्यान लगा सकते हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सितंबर में कहा कि भारत और अमेरिका के बीच सीमित व्यापार समझौता करने के मामले में जितने भी मुद्दे आड़े आ रहे थे उनका समाधान कर लिया गया है इसके बाद अमेरिका की राजनीतिक स्थिति यदि इसकी अनुमति देती है तो किसी भी समय यह समझौता हो सकता है। भारत की ओर से अमेरिका के समक्ष जो मांगे रखी गई थी उनमें इस्पात और एल्यूमीनियम उत्पादों पर लगाये जा रहे ऊंचे शुल्क से छूट देने, जीएसपी के तहत भारत को कुछ निर्यात सामानों पर दिये जाने वाले लाभ को बहाल करने पर जोर दिया गया। इसके अलावा कृषि, आटोमोबाइल, वाहन कलपुर्जे और इंजीनियरिंग उत्पादों को अमेरिका में बेहतर बाजार पहुंच उपलब्ध कराने को कहा गया। दूसरी तरफ अमेरिका की ओर से भारत के बाजारों में उसके कृषि और विनिर्मित उत्पादों, डेयरी सामानों और चिकित्सा उपकरणों के लिये अधिक बाजार पहुंच उपलब्ध कराने और साथ ही कुछ सूचना और दूरसंचार प्रौद्योगकी के उत्पादों पर आयात शुल्क कम करने की मांग की गई।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की 29 परियोजनाओं को मंजूरी, 15,000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद

नयी दिल्ली। एजेंसी

खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि उसने विभिन्न राज्यों में 29 परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं में 500 करोड़ रुपये से अधिक निवेश होने और करीब 15,000 रोजगार सृजन की उम्मीद है। आधिकारिक बयान के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में हुई अंतर-मंत्री स्तरीय स्वीकृति समिति (आईएमएसी) की बैठक में 443 करोड़ रुपये की निवेश लागत वाली 21 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसे एकीकृत शीत गृह श्रृंखला और मूल्य वर्धन योजना के तहत 189 करोड़ रुपये के अनुदान के जरिये मदद दी जाएगी। तोमर की अध्यक्षता में हुई एक और बैठक में आठ और परियोजनाओं को मंजूरी दी गयी। इन परियोजनाओं में 62 करोड़ रुपये का निवेश अनुमानित है। इनके लिए बीएफएल (बैकवार्ड और फारवार्ड लिंकेज) योजना के तहत 15 करोड़ रुपए का अनुदान मंजूर किया गया। बैठक में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रामेश्वर तेली भी उपस्थित थे। बयान के अनुसार तोमर ने कहा कि इन परियोजनाओं से किसानों और उपभोक्ताओं को लाभ होगा। उन्होंने अधिकारियों से इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने का आग्रह किया। मंत्रालय के अनुसार 21 परियोजनाओं से लगभग 12,600 लोगों के लिए रोजगार सृजित होने और 2,00,592 किसानों को लाभ होने की संभावना है। ये परियोजनाएं 10 राज्यों- आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, केरल, नागालैंड, पंजाब, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में फैली हुई हैं। एकीकृत शीत गृह श्रृंखला और मूल्य वर्धित बुनियादी ढांचे की योजना का उद्देश्य बागवानी और गैर-बागवानी उत्पादों की कटाई के बाद के नुकसान पर रोक लगाना और किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करना है। बयान के अनुसार दूसरी बैठक में मंजूर की गयी आठ परियोजनाओं से लगभग 2,500 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।

भारत में महामारी के दौरान लिवर और किडनी का संयुक्त ट्रांसप्लांट (लाइव डोनर) सफल

दिल्ली से चेन्नई तक, निराशा से आशा की यात्रा

चेन्नई। एजेंसी

ग्लेनईगल्स ग्लोबल हेल्थ सिटी (जीजीएचसी), एशिया के प्रमुख मल्टी-ऑर्गन ट्रांसप्लांट सेंटर, ने कोविड-19 महामारी के दौरान दो लाइव डोनर्स की मदद से भारत में पहला लिवर एवं किडनी ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक किया है। 35 वर्षीय श्री मित्तल को दिल्ली से जीजीएचसी एयरलिफ्ट किया गया था, जिन्हें रीनल फेलियर और लिवर की एक पुरानी समस्या, फैटी लिवर की शिकायत थी। इस कारण उन्हें किडनी एवं लिवर ट्रांसप्लांट की अत्यंत आवश्यकता थी। नई दिल्ली के एक अस्पताल में उनके इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उनके स्वास्थ्य की स्थिति के कारण ट्रांसप्लांट सर्जरी को टालने का फैसला किया था, क्योंकि उन्हें कार्डियक शॉक और लो बीपी भी था। हालांकि उनका परिवार आशंका में था और उसने सेकंड ओपिनियन के लिये जीजीएचसी की लिवर ट्रांसप्लांट टीम से संपर्क किया और जीजीएचसी, चेन्नई में इलाज करवाने का फैसला किया। दिल्ली से चेन्नई जाने की पूरी प्रक्रिया बहुत चुनौतीपूर्ण थी, क्योंकि रोगी को कई समस्याएं थीं और वह मोटापे (130 किलोग्राम) से भी ग्रस्त थे, लेकिन इसका समन्वय बाधारहित तरीके से किया गया।

जीजीएचसी आने पर, रोगी लो बीपी के कारण बेहोश थे और उन्हें डायलिसिस पर रखा जाना था। जीजीएचसी की मेडिकल टीम ने उनकी जाँच की और कई अन्य समस्याओं के अलावा उनके खून में फंगल ग्रोथ भी पाई और इसलिये उन्हें 2 सप्ताह के लिये स्पेशियलाइज्ड लिवर आईसीयू यूनिट में एडमिट किया गया और आवश्यक सहयोगी मेडिकल केयर दी गई, जिसमें एंटी-फंगल ट्रीटमेन्ट और 3-4 दिन के लिये चौबीसों घंटे डायलिसिस शामिल था। इस बीच, रोगी की पत्नी और बहन का संपूर्ण चिकित्सकीय परीक्षण किया गया, यह जानने के लिये कि वे क्रमशः लिवर डोनर और किडनी डोनर बन सकती हैं या नहीं।

इस सर्जरी की सफलता के बारे में डॉ. ज्वॉय वर्गीस, डायरेक्टर- हीपैटोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट हीपैटोलॉजी, ग्लेनईगल्स ग्लोबल हेल्थ सिटी ने कहा, "लाइव डोनर लिवर एवं किडनी ट्रांसप्लांट की यह संयुक्त सर्जरी 14 घंटे से ज्यादा समय तक चली, जिसमें लिवर, रीनल और क्रिटिकल केयर स्पेशियलिस्ट्स की एक टीम शामिल थी। सफल ड्यूअल ऑर्गन ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद रोगी को होश आया और बाद में उन्हें अपने परिवार से पता चला कि उन्हें चेन्नई एयरलिफ्ट किया गया था और उनका इलाज जीजीएचसी में हुआ। सर्जरी के बाद 16वें दिन रोगी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। रोगी और उनकी बहन तथा पत्नी पूरी तरह से तंदुरूस्त और स्वस्थ हैं।"

डॉ. रजनीकांत पटचा, क्लिनिकल लीड- लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी, ग्लेनईगल्स ग्लोबल हेल्थ सिटी ने कहा, "इस तरह की कठिन सर्जरी केवल अस्पताल के समर्पित बहुविषयक अप्रोच के कारण संभव हो सकी। मैं श्री नितिन को सकरात्मक और बहादुर होने के लिये धन्यवाद देता हूँ। रोगी को बचाने की मजबूत इच्छा और प्रेरणा और हम पर भरोसा करने के लिये उनकी पत्नी और बहन को खासतौर से धन्यवाद। यह केस हमारी संस्कृति और हमारे देश के महान पारिवारिक मूल्यों और परिजनों की 'कभी हार न मानने' वाली सोच की अच्छी समझ देता है।" डॉ. सेल्वाकुमार मल्लीस्वरन, लिवर आईसीयू के हेड- ग्लेनईगल्स ग्लोबल हेल्थ सिटी ने कहा, "हमने रोगी का ब्लड प्रेशर सुधारने के लिये एडवांस्ड कार्डियक आउटपुट

मॉनिटरिंग का उपयोग किया और उनके शरीर से लगभग 20 लीटर अनावश्यक तरल निकाला। क्रिटिकल केयर स्पेशियलिस्ट्स और नर्सों की एक समर्पित टीम ने सुनिश्चित किया कि रोगी और दोनों डोनर्स कोविड संक्रमण से सुरक्षित रहें।"

ग्लेईगल्स ग्लोबल हेल्थ सिटी में यूरोलॉजी के सीनियर कंसल्टेन्ट और रीनल ट्रांसप्लांटेशन सर्जन डॉ. के. मुरूगानंधम एवं नेफ्रोलॉजी के सीनियर कंसल्टेन्ट और रीनल ट्रांसप्लांट फिजिशियन डॉ.पी. मुथुकुमार ने कहा, "महामारी के दौरान लिविंग डोनर रीनल ट्रांसप्लांट करने में हमने कई चुनौतियों का सामना किया। रोगी और डोनर, दोनों मोटे थे, संक्रमण पर नियंत्रण के उच्च स्तरीय उपाय किये जाने थे और कई कंसल्टेन्ट्स, तकनीशियनों, पैरामेडिक्स और सपोर्ट स्टाफ के बीच लगातार समन्वय की जरूरत थी। इतने कम बीपी वाले रोगी का डायलिसिस करना एक बड़ी चुनौती थी और सर्जरी के पहले और बाद में 'कंटिन्यूअस रीनल रिप्लेसमेन्ट थेरैपी' देनी थी। सर्जरी से पहले की सर्वश्रेष्ठ संभव सावधानियाँ रखते हुए हमने रीनल डोनर से कीहोल किडनी रिट्रीवल किया और उसे रोगी में सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट कर दिया। कई समस्याओं के बावजूद किडनी ने इम्प्लांटेशन के तुरंत बाद मूत्र बनाना शुरू कर दिया। डोनर्स और रोगी की सकारात्मकता ने बहुत जल्दी और सुचारू रिकवरी में योगदान दिया।" यह पथप्रदर्शक प्रत्यारोपण डॉ. ज?वॉय वर्गीस, डायरेक्टर- हीपैटोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट हीपैटोलॉजी, डॉ. रजनीकांत पटचा, क्लिनिकल लीड- लीवर ट्रांसप्लांट सर्जरी, ग्लेनईगल्स ग्लोबल हेल्थ सिटी, डॉ. सेल्वाकुमार मल्लीस्वरन, हेड - लिवर आईसीयू, डॉ. के. मुरूगानंधम, सीनियर कंसल्टेन्ट- यूरोलॉजी एवं रीनल ट्रांसप्लांटेशन सर्जन और डॉ. पी. मुथुकुमार, सीनियर कंसल्टेन्ट- नेफ्रोलॉजी एंड रीनल ट्रांसप्लांट फिजिशियन, के नेतृत्व में हुआ।

धनतेरस से पहले सस्ता हुआ सोना, चांदी की कीमतों में भी बड़ी गिरावट

नई दिल्ली। एजेंसी

कोरोना वायरस की वैक्सीन आने की खबर से बुधवार को भी सोने और चांदी (Gold silver price today) की कीमतों में नरमी देखने को मिली है। कमोडिटी एक्सचेंज में गोल्ड फ्यूचर्स 91 रुपये यानी 0.18 फीसदी गिरकर 50,410 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था। सिल्वर फ्यूचर्स भी 287 रुपये यानी 0.34 फीसदी की नरमी के साथ 62,832 रुपये प्रति किलोग्राम था। वहीं, भारतीय बाजार में गोल्ड और सिल्वर 10 नवंबर को तेजी के साथ बंद हुए थे।

वैक्सीन की खबर से गिरे सोने-चांदी के भाव

सोमवार को कोरोना वायरस की वैक्सीन की खबर आने से गोल्ड और सिल्वर में भारी बिकवाली देखने को मिली। निवेशक सोने में से पैसा निकाल कर स्टॉक मार्केट की तरफ बढ़ रहे हैं। जानकारों का कहना है कि प्रॉफिट बुकिंग के कारण गोल्ड-सिल्वर में गिरावट आई, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से इसकी वैल्यू बरकरार है।

50 हजार रुपए हो सकता है सपोर्ट लेवल

मार्केट एक्सपर्ट यह सलाह दे रहे हैं कि निवेशक हर गिरावट पर गोल्ड में खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल इस समय गोल्ड का अहम सपोर्ट लेवल करीब 50 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम पर नजर आ रहा है।

डॉलर के कमजोर रहने से मिलता है गोल्ड को सपोर्ट

जानकारों के मुताबिक, अमेरिका में राहत पैकेज बढ़ने की उम्मीद और डॉलर के कमजोर रहने से गोल्ड की कीमतों को सपोर्ट मिलता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विकसित देशों में मॉनेटरी पॉलिसी को आसान बनाने से आने वाले महीनों में इनफ्लेशन बढ़ सकता है।

कितना है गोल्ड-सिल्वर का सपोर्ट लेवल?

सूत्रों के अनुसार MCX में गोल्ड का सपोर्ट लेवल 50330-50000 रह सकता है जबकि इसका रेजिस्टेंस 50800-51000 लेवल पर रह सकता है। वहीं, चांदी की बात करें तो इसका सपोर्ट लेवल 62500-61800 है जबकि इसका रेजिस्टेंस लेवल 63660-64400 है। निवेशक गोल्ड को 50,000 रुपए के लेवल में और सिल्वर को 61800 रुपए के लेवल में खरीद सकते हैं।

किस वजह से सोने के दामों में आई गिरावट

अमेरिकी फार्मा कंपनी फाइजर और उसकी जर्मनी की पार्टनर कंपनी BioNTech SE का दावा है कि कोरोना वायरस वैक्सीन तीसरे चरण के ट्रायल में 90 फीसदी प्रभावी है। कोरोना काल में यह दो कंपनियां पहली ऐसी कंपनी हैं जिन्होंने वैक्सीन के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल और सफल परिणाम का आंकड़ा पेश किया है। फाइजर का कहना है कि वह अपनी टू-डोज वैक्सीन के इमर्जेंसी अथराइजेशन के लिए USFDA से इसी महीने अनुमति लेगी। मगर उससे पहले कंपनी दो महीने का सेफ्टी डेटा कलेक्ट करेगी। इस दौरान, 164 कन्फर्म मामलों पर क्लिनिकल ट्रायल चलते रहेंगे ताकि वैक्सीन की परफॉर्मेंस का और बेहतर ढंग से आंका जा सके। फाइजर ने कहा है कि स्टडी में वैक्सीन का एफिसेसी पर्सेंटेज बदलता रह सकता है।

विदेशी मुद्रा भंडार 18.3 करोड़ डॉलर बढ़कर 560.72 अरब डॉलर पर पहुंचा

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

देश का विदेशी मुद्रा भंडार 30 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में 18.3 करोड़ डॉलर बढ़कर 560.715 अरब डालर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को इसके आंकड़े जारी किए। इससे पिछले 23 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 5.41 अरब डॉलर बढ़कर 560.53 अरब डॉलर रहा था। समीक्षावधि में विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ने की अहम वजह विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों (एफसीए) का बढ़ना है। एफसीए कुल विदेशी मुद्रा भंडार का अहम हिस्सा होता है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार समीक्षावधि में एफसीए 81.5 करोड़ डॉलर बढ़कर 518.34 अरब डॉलर हो गया। एफसीए को दर्शाया डॉलर में जाता है, लेकिन इसमें यूरो, पौंड और येन जैसी अन्य विदेशी मुद्राएं भी शामिल होती है। इस दौरान देश का स्वर्ण भंडार 60.1 करोड़ डॉलर घटकर 36.26 अरब डॉलर का रह गया। देश को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से मिला विशेष आहरण अधिकार 60 लाख डॉलर घटकर 1.482 अरब डॉलर रह गया। वहीं, समीक्षावधि में देश का आईएमएफ के पास जमा मुद्रा भंडार 2.5 करोड़ डॉलर घटकर 4.64 अरब डॉलर रह गया।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।